ई-संदेश

14 जुलाई 2021, वर्ष 4, अंक 147

सात दिन - सात पृष्ठ

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय में उनकी प्रतिमा के सम्मुख माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

- ★ प्रदेश के विकास में औद्योगिक गतिविधियों का विशेष योगदान है
- ★ 'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रही है
- ★ जनसंख्या नीति का सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाने से है
- ★ तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की क्षमताएं उच्च गुणवत्ता की हों
- ★ त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका
- ★ शिवालयों और शिव मंदिरों में भी प्रकाश सहित उत्कष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं
- ★ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की
- ★ 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' से गरीब पटरी व्यवसायियों को मदद मिल रही
- ★ कोरोना कालखण्ड में ओलम्पिक खिलाड़ियों के प्रयासों से नई पीढ़ी को स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिलेगी

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

कोरोना हारेगा भारत जीतेगा

प्रदेश के विकास में औद्योगिक गतिविधियों का विशेष योगदान है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष सरकारी आवास पर 'रिव्यु ऑफ मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज बर्डेन' विषयक प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक कानूनों से सम्बन्धित सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों के समाधान के लिए टाइम लाइन निर्धारित करते हुए समयबद्धता से इनका निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इन प्रकरणों के समाधान के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही की निरन्तर मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को इस कार्य की नियमित समीक्षा करने के लिए कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' तथा 'ईज ऑफ लिविंग' को पूरी तरह से लागू करना चाहती है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को त्वरित गति से संचालित किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। प्रदेश के विकास में औद्योगिक गतिविधियों का विशेष योगदान है। इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होता है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत अनावश्यक कानूनों से सम्बन्धित सभी विभागों के लम्बित प्रकरणों का समाधान निर्धारित तिथि तक हर हाल में कर दिया जाए। जिन नियमध्कानूनों को रिपील किया जाना है, उनके सम्बन्ध में तेजी से कार्यवाही करके इन्हें समाप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण करते हुए अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविन्द कुमार ने अवगत कराया कि 'मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज बर्डेन' पहल केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर, 2020 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य निर्धारित मापदण्डों पर 'मिनिमाइजिंग रेगुलेटरी कॉम्प्लायन्सेज बर्डेन' को कम करना था। इस पहल से 'ईज ऑफ डुईंग बिजनेस' और 'ईज ऑफ लिविंग' पर विशेष बल दिया गया।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि इस पहल के दो चरण हैं। पहला चरण 31 मार्च, 2021 में लागू हुआ जबकि दूसरा चरण 15 अगस्त, 2021 से लागू होगा। उन्होंने बताया कि इन दोनों चरणों के तहत 675 कॉम्प्लायन्सेज को चिन्हित किया गया। इन विभागों में श्रम, आबकारी, ऊर्जा, वन, रेरा, पर्यावरण, खाद्य एवं रसद, प्राथमिक शिक्षा, पंचायती राज, उच्च शिक्षा, हैण्डलूम तथा वस्त्रोद्योग, गृह, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, आवास, मत्स्य, सिंचाई तथा जल संसाधन, तकनीकी शिक्षा, परिवहन एवं नगरीय विकास शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मनोज सिंह, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्रीमती मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉ रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव वन सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रही है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि 'ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट' नीति कोरोना संक्रमण की रोकथाम में अत्यन्त कारगर सिद्ध हो रही है। इस नीति को पूरी सक्रियता से लागू रखा जाए।

मुख्यमंत्री लोक भवन में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड–19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 96 नए मामले सामने आये हैं। इसी अवधि में 112 संक्रमित व्यक्तियों को सफल उपचार के बाद डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में राज्य में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1576 है।

मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि पिछले 24 घण्टों में प्रदेश में 2 लाख 28 हजार 866 कोरोना टेस्ट किये गये हैं। राज्य में अब तक 6 करोड़ 8 लाख 45 हजार 909 कोरोना टेस्ट किये जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद सुलतानपुर व सीतापुर में नये केस की संख्या बढ़ी है। इसके दृष्टिगत दोनों जनपदों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। उन्होंने कहा कि संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी भी प्राप्त की जाए तथा इनके सम्पर्क में आए लोगों की अधिक से अधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सुविधाजनक ढंग से हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि प्रदेश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ 71 लाख 82 हजार से अधिक डोज लगायी जा चुकी हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि आगामी 8 से 10 माह के लिए कार्य योजना तैयार करे, जिससे लोगों को सुविधाजनक ढंग से स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त हो सकें । उन्होंने कहा कि सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की रंगाई–पुताई, मेडिकल उपकरणों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए। इसके साथ ही, स्वास्थ्य केन्द्रों में मानव संसाधन की भी समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सीएचसी/पीएचसी स्तर पर हेल्थ एटीएम की स्थापना करायी जाए। अनेक औद्योगिक संस्थान प्रदेश में हेल्थ एटीएम स्थापित करना चाहते हैं। हेल्थ एटीएम स्थापित हो जाने से लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को उपचार की सुगम सुविधा प्राप्त हो सके। इसके तहत डायलिसिस, कैंसर के उपचार सहित अन्य रोगों के इलाज की व्यवस्था करायी जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी किए गए विशेष हेल्पलाइन नम्बर 14567 का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य पूरी तत्परता से संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से देश में पीएम कुसुम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसके लिए कार्ययोजना बनायी जाए।

जनसंख्या नीति का सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाने से है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नीति का सम्बन्ध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली एवं समृद्धि लाने से है। जनसंख्या स्थिरीकरण का प्रयास समाज में इसके प्रति जागरूकता से जुड़ा हुआ है। समाज के विभिन्न तबकों में गरीबी का भी जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्ध है। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए व्यापक जागरूकता अभियान संचालित करना होगा।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर विश्व जनसंख्या दिवस व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा (11 जुलाई से 24 जुलाई, 2021) के अवसर पर 'जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश 2021–30' के विमोचन के उपरान्त अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के 11 जनपदों में स्थापित बीएसएल0–2 आरटीपीसीआर प्रयोगशालाओं एवं 'उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्र' एप का शुभारम्भ भी किया। उन्होंने 2 नव दम्पतियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'शगुन किट' भी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर केन्द्रित एक फिल्म भी प्रदर्शित की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या को विकास में बाधक होने पर निरन्तर चर्चा हो रही है। जहां भी जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समन्वित प्रयास हुए हैं, वहां सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021–30 जारी की गयी है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा देश में इन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश द्वारा भी इस दिशा में आवश्यक रूप से प्रयास करना होगा। वर्ष 2019 में गांधी जयन्ती के अवसर पर राज्य विधान मण्डल द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए रिकॉर्ड 36 घण्टे तक लगातार चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु समितियां गठित की गयीं। इस सम्बन्ध में प्रगति की मंत्रिमण्डल के एक समूह द्वारा समीक्षा की जाती है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इनके सम्बन्ध में जनसमुदाय में जागरूकता के भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 4 वर्षों में राज्य में टोटल फर्टिलिटी रेट (टीएफआर), मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो (एमएमआर) एवं इन्फैण्ट मॉर्टेलिटी रेट (आईएमआर) को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों में पर्याप्त सफलता भी प्राप्त हुई है। किन्तु देश में टीएफआर, एमएमआर एवं आईएमआर के आंकड़ों को देखते हुए इस दिशा में और भी प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में राज्य में टीएफआर 3.3 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। वर्तमान में यह घटकर राज्य में 2.7 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 2.3 हो गया है। इसी प्रकार वर्ष 2016 में प्रदेश में एमएमआर 258 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 178 था। वर्तमान में यह कम होकर राज्य में 197 तथा राष्ट्रीय स्तर पर 113 हो गया है। आईएमआर में भी कमी आयी है। वर्ष 2016 में राज्य में यह 53 एवं राष्ट्रीय स्तर पर 42 था, जो वर्तमान में घटकर क्रमशः 43 एवं 33 हो गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 बच्चों के मध्य अन्तराल न होने पर उनके पोषण पर प्रभाव पड़ेगा। इससे मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होगी। विगत वर्षों में इनसे सम्बन्धित लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों में अच्छी सफलता मिली है, किन्तु इन प्रयासों को अभी और प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या स्थिरता की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के साथ ही यह भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है कि इसका देश की जन सांख्यकी पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की क्षमताएं उच्च गुणवत्ता की हों : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष सरकारी आवास पर प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) द्वारा एआईसीटीई विनियम–2019 के लागू होने के उपरान्त अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं की विनियमावली में प्रस्तावित संशोधन तथा फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 'राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति' (एनओसी) प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप ही पॉलीटेक्निक/फार्मेसी के कोर्स डिजाइन किए जाएं। उन्होंने कहा कि डिमाण्ड के अनुसार ही इन संस्थाओं द्वारा संचालित कोर्सों को अपग्रेड करना आवश्यक है। इसके साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, अन्यथा अच्छी जनशक्ति की उपलब्धता के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में उपलब्ध रोजगार के दृष्टिगत पॉलीटेक्निक संस्थानों द्वारा संचालित कोर्सों को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की अच्छी मांग है। आवश्यकता इस बात की है कि तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों की क्षमताएं उच्च गुणवत्ता की हों। इससे उनके रोजगार पाने की सम्भावनाएं बढ़ जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत फार्मा सेक्टर में फार्मा कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों की अच्छी मांग है। उन्होंने फार्मा के कोर्सों को समय की मांग के अनुसार अद्यतन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फार्मा कोर्स पासआउट्स की भविष्य में अच्छी डिमाण्ड रहेगी। उनके रोजगार पाने की प्रबल सम्भावनाएं मौजूद हैं। अतः फार्मा कोर्सों को तत्काल अद्यतन किया जाए।

मुख्यमंत्री के समक्ष सचिव प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार ने प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रम में राजकीय एवं अनुदानित/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं में शैक्षणिक पदों हेतु एआईसीटीई के विनियम 2019 के अनुसार सातवें वेतनमान की संस्तुतियों को लागू किये जाने और इसके अनुक्रम में राजकीय एवं अनुदानित पॉलीटेक्निक संस्थाओं की सेवा नियमावली/विनियमावली बनाए जाने का निर्णय लिया गया था।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रम में राजकीय एवं अनुदानित/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं की शैक्षणिक पदों हेतु सेवा नियमावली/विनियमावली बनाए जानेध्संशोधन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव अलग–अलग संचालित किए गए।

मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 23 जून, 2021 को प्रधानाचार्यों, कर्मशाला अधीक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के कुल 1,357 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन भेजा जा चुका है। इस पर मुख्यमंत्री ने इन पदों पर शीघ्र तैनाती की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अनुदानित/सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थाओं हेतु विद्यमान विनियमावली–1996 (यथासंशोधित) में संशोधन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री को फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 'राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति' (एनओसी) प्रदान करने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए सचिव प्राविधिक शिक्षा ने कहा कि वर्तमान में पीसीआई द्वारा वर्ष 2019 में फार्मेसी के नवीन संस्थाओं की स्थापना पर अनुमोदन देने पर 5 वर्ष तक रोक लगायी गयी है। पीसीआई द्वारा फार्मेसी की पूर्व से संचालित संस्थाओं में 'प्रवेश क्षमता में वृद्धि' एवं 'नये फार्मेसी पाठ्यक्रम को संचालित' करने में छूट प्रदान की गयी है।

मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पीसीआई ने अपने 31 दिसम्बर, 2020 के सर्कुलर में यह प्राविधानित किया है कि यदि राज्य सरकार शासनादेश जारी कर एनओसी की व्यवस्था को समाप्त करती है तो अलग से राज्य सरकार द्वारा संस्थाओं को एनओसी निर्गत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायत के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में विकास के महत्वपूर्ण कार्य संचालित होते हैं। उन्होंने क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों से पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण भाव से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की है।

मुख्यमंत्री ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनके द्वारा दिए गए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के मंत्र से पिछले सवा चार वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया गया। केन्द्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में सरकार ने जन–जन तक विभिन्न योजनाओं को पहुंचाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद से ग्राम पंचायतों का बजट बढ़ा है। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायतों में काफी सुधार हुए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विकास की प्रक्रिया से सभी पंचायतों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान व उनके सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना सक्रिय योगदान देंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गांव, गरीब और किसान की सीधी मदद करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने समस्त नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कोरोना कालखण्ड की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में स्थानीय प्रशासन को सहयोग प्रदान करते हुए मानवता की सेवा में सहभागी बनने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत के सभी 75 अध्यक्षों को और 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को बधाई देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय व क्षेत्र पंचायत चुनाव के परिणाम आज सामने आए हैं। 26 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी और उसके बाद 4 चरणों में चुनाव सम्पन्न हुए। जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 में चुनाव सम्पन्न हुए। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 के चुनाव सम्पन्न हुए। 7,32,485 ग्राम पंचायत समिति के सदस्य चुने गए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 सीटों पर चुनाव सम्पन्न हुए। मतगणना अपने अन्तिम चरणों में है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव सम्पन्न हुए थे, जिनमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव विगत सप्ताह सम्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव के रूप में इसे देखा जा सकता है। उन्होंने इन सभी चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़कर जन विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की यह प्रक्रिया सम्पन्न हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग का विशेष रूप से अभिनन्दन करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के इस कालखण्ड में पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक चार चरणों में सम्पन्न किया गया। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल व 29 अप्रैल, 2021 को यह चुनाव सम्पन्न हुए। इस चुनाव को सम्पन्न कराने में 10,12,395 मतदान कर्मियों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस, होमगार्ड, पीएसी के जवानों ने मिलकर लोकतंत्र के सबसे बड़े आयोजन के द्वारा 8 लाख 70 हजार से अधिक जनप्रतिनिधियों का चुनाव सम्पन्न कराने और इस पूरी प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान कुछ लोग कोरोना की चपेट में आए तथा कुछ की दुःखद मृत्यु भी हो गई। चुनाव ड्यूटी करते हुए जिन दिवंगत कर्मियों ने लोकतंत्र को मजबूत किया, उन सभी के प्रति उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिवंगत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।

शिवालयों और शिव मंदिरों में भी प्रकाश सहित उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास में भगवान शिव के भक्तों की पवित्र कांवड़ यात्रा–2021 की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की आज समीक्षा की। उन्होंने कहा कि श्रावण मास 25 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ हो रहा है। इसके दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न जनपदों व मार्गों पर श्रद्धालुगण द्वारा निकाली जाने वाली कांवड़ यात्राओं के सम्बन्ध में सभी तैयारियां समय से सुनिश्चित कर ली जाएं। इन यात्राओं में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो। कांवड़ यात्राओं के सुरक्षित, सकुशल एवं सफल संचालन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोताही न हो। उन्होंने कहा कि श्रावण मास के प्रारम्भ होने के पूर्व बकरीद का भी त्यौहार पड़ रहा है। इसके दृष्टिगत सतर्कता और सावधानी आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत प्रत्येक स्तर पर कांवड़ संघों से संवाद स्थापित किया जाए। अनावश्यक भीड़ न एकत्र हो। कोविड के सम्बन्ध में सतर्कता व सावधानी के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

उन्होंने कहा कि कोविड की सेकेण्ड वेव पर नियंत्रण हुआ है, किन्तु सावधानी हर स्तर पर बरतना आवश्यक है। उन्होंने जन–भावनाओं और आस्था का सम्मान करते हुए कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड के दृष्टिगत कोविड हेल्प डेस्क, कोविड केयर सेण्टर, एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल में आरक्षित बेड आदि उपलब्ध रहें। इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर की भी व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रियों व यात्राओं के सम्बन्ध में की जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिव मंदिरों, शिवालयों, देव मंदिरों, यात्रा मार्गों सहित ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की साफ–सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्ट्रीट लाइट सुनिश्चित की जाए। इन मार्गों पर बिजली के तार झूलते हुए न मिलें।

यातायात व्यवस्था को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। संवेदनशील स्थलों के सम्बन्ध में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करते हुए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखी जाए। शिवालयों, कावंड़ यात्रियों के लंगर स्थलों, विश्रामालयों आदि स्थलों पर भी विशेष सतर्कता रखी जाए। सड़क व नदी आदि में होने वाली दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में भी तैयारी कर ली जाए। शिवालयों और शिव मंदिरों में भी प्रकाश सहित उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे कांवड़ यात्री मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर सकें। विद्युत आपूर्ति और पेयजल सहित यात्रियों के लिए जन–सुविधाओं की भी उपलब्धता रहे।

मुख्यमंत्री ने धार्मिक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं व संगठनों से समन्वय व संवाद स्थापित करते हुए कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सौहार्द व शांतिपूर्ण वातावरण में कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर सभी मण्डलायुक्तों और पुलिस जोन के वरिष्ठ अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने मण्डलायुक्तों तथा पुलिस जोन के अधिकारियों को जनपद तथा रेंज स्तर पर तैयारियों व सतर्कता के सम्बन्ध में बैठकें किए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक मुकुल गोयल, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं सूचना संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को शिक्षा के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान की : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयन्ती के अवसर पर आज यहां डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय के परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा के सम्मुख चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत माता के महान सपूत, प्रखर राष्ट्र भक्त एवं महान शिक्षाविद थे। डा मुखर्जी की जयन्ती के अवसर पर आज पूरा राष्ट्र देश के प्रति उनके सेवाओं के लिए स्मरण कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डा मुखर्जी भारत की एकता और अखण्डता के प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने देश की अखण्डता के लिए अन्तिम सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखी तथा इसी के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डा मुखर्जी के सपनों को साकार स्वरूप प्रदान करते हुए 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर दिया। आज जम्मू और कश्मीर विकास की एक नई उमंग के साथ देश में शान्ति और सौहार्द के एक नये युग की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डा मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देश को एक नई दिशा प्रदान की थी। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत में डा मुखर्जी ने देश को एक विजन दिया था। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही देश में औद्योगिक विकास की गति दिखाई दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डा मुखर्जी का देश के विकास, भारत की एकता और अखण्डता तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख योगदान है। उन्होंने डा मुखर्जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डा मुखर्जी के सपनों का भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के रूप में आज दुनिया के सामने एक नई मिसाल प्रस्तुत कर रहा है।

इस अवसर पर जलशक्ति और बाढ़ नियंत्रण मंत्री डा महेन्द्र सिंह, विधायी और न्याय मंत्री बृजेश पाठक, नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, महिला कल्याण एवं बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाति सिंह, विधान परिषद सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह, लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' से गरीब पटरी व्यवसायियों को मदद मिल रही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद जनसंख्या नीति का सम्बन्ध प्रत्येक गोरखपुर में योगीराज बाबा गम्भीरनाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केन्द्र में आयोजित कुल 8025.47 लाख रुपए की लागत की 123 अवस्थापना विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इनमें 3953.53 लाख रुपए की 48 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 4071.94 लाख रुपए की लागत की 75 परियोजनाओं का लोकार्पण सम्मिलित है। यह परियोजनाएं विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, सहजनवा, बासगांव, खजनी के विकास कार्यों की है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विकास किसी क्षेत्र विशेष हेतु सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जनपद के जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। विकास के लिए धन की कमी नहीं है, आवश्यकता है कि उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध ढंग से सदुपयोग किया जाए। विकास हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन, खुशहाली एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकास का कोई विकल्प नहीं होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी योजनाएं जनहित में संचालित की जाती हैं, उनका लाभ पात्र जन को समय से उपलब्ध कराया जाए और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के बजाए सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की स्वीकृत योजनाओं में समग्रता छिपी होती है। सबका साथ और सबका विकास का भाव निहित होता है। हम सबका दायित्व है कि स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाए, यह हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के साथ–साथ विकास की परियोजनाओं को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। जीवन के साथ ही जीविका को भी बचाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना कमजोर हुआ है समाप्त नहीं, इसके प्रति लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति मास्क पहने यह सुरक्षा प्रदान करता है और मास्क तमाम प्रकार के इंफेक्शन से बचाने में सफल है, इसके प्रति सभी को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कालखण्ड के दौरान कोरोना नियंत्रण में निगरानी समितियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यह समितियां मेडिकल किट वितरण से लेकर घर–घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य कर रही हैं। निगरानी समितियों से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित करना हमारा दायित्व बनता है, सभी के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखते ही इसे छिपाने के बजाए जांच कराकर उपचार कराएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के नियमों, मापदण्ड का पालन करते हुए वैक्सीनेशन हर व्यक्ति अवश्य कराए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था प्रदान की है। वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का सुरक्षा कवच है और सतर्कता व सावधानी ही इस महामारी से बचाव है। केन्द्र सरकार 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, इसका लाभ हर पात्र जन को पहुंचाया जाए। हम सभी को निर्बाध रूप से इन योजनाओं का स्वागत करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता–पिता को खोया है, ऐसे बच्चों के कानूनी अभिभावक के बैंक खाते में 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत जल्द ही 4,000 रुपए दिए जाएंगे और निःशुल्क आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही, कोरोना के कारण निराश्रित महिलाओं को पेंशन तथा उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर रह सकें। केन्द्र व प्रदेश सरकार उनके सहयोग हेतु तत्पर है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां शुरू हो गयी है, बच्चों को मेडिसिन किट वितरण के साथ ही सफाई, सैनिटाइजेशन आदि की कार्यवाही चल रही है।

कोरोना कालखण्ड में ओलम्पिक खिलाड़ियों के प्रयासों से नई पीढ़ी को स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिलेगी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में टोक्यो ओलम्पिक में हिस्सा लेने वाले उत्तर प्रदेश के 10 खिलाड़ियों– प्रियंका गोस्वामी, अन्नू रानी, सीमा पुनिया, वंदना कटारिया, सौरभ चौधरी, मेराज अहमद खान, अरविन्द सिंह, सतीश कुमार, श्री शिवपाल सिंह एवं ललित कुमार उपाध्याय से वर्चुअल वार्ता कर उनका मनोबल बढ़ाया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के इस कालखण्ड में ओलम्पिक खिलाड़ियों के प्रयासों से नई पीढ़ी को स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिलेगी। इनके द्वारा देश एवं प्रदेश का मान बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास नई पीढ़ी के लिए अनुकरणीय होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ओलम्पिक में एकल खेल में स्वर्ण पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक लाने वालों को 4 करोड़ तथा कांस्य पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए, प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए तथा टीम खेल में स्वर्ण पदक लाने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक लाने पर 2 करोड़ रुपए, कांस्य पदक लाने पर 1 करोड़ रुपए एवं प्रतिभाग करने पर 10 लाख रुपए का सहयोग करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा है कि अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ना चाहिए और अलग–अलग फील्ड के प्रतिभाशाली लोगों को सरकार की ओर से एक मंच मिलना चाहिए। केन्द्र एवं राज्य सरकार इसी दिशा में प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 'खेलो इंडिया' के माध्यम से देश एवं प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जो अभिनंदनीय है। इसी कड़ी को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है। इसके अन्तर्गत राजस्व विभाग, पंचायती राज, खेल विभाग, ग्राम विकास विभाग मिलकर हर गांव मे खेल का मैदान तैयार कर रहे हैं। साथ ही, यह भी निर्देश दिये गये हैं कि खेल के मैदान के साथ–साथ ओपन जिम का भी निर्माण हो, जिससे युवा पीढ़ी की खेल के प्रति रुचि बढ़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'खेलो इंडिया' के तहत अभी हर स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं, जिससे नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज व गांव में अलग–अलग स्तर पर यह कार्यक्रम चल रहा है।

उन्होंने कहा कि खेल का मैदान, स्टेडियम, मिनी स्टेडियम का निर्माण एवं स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करायी जा रही है। प्रदेश सरकार के युवा कल्याण विभाग द्वारा हर गांव में युवक मंगल दल गठित करने के साथ उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। यह अभियान निरन्तर आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जायेगी। यह यूनिवर्सिटी सभी खिलाड़ियों को जोड़कर उनकी प्रतिभाओं एवं ऊर्जा का लाभ राज्य के युवाओं को आगे बढ़ने एवं एक नये मंच को प्रदान करने में सहायक होगी।

इस अवसर पर के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपेन्द्र तिवारी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, निदेशक खेल आरपी सिंह आदि वर्चुअल रूप से जुड़े रहे।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक शिशिर, आईएएस द्वारा प्रकाशित
प्रभारी सम्पादक : डॉ. सीमा गुप्ता